The House reassembled at one of the clock,

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

THE BUDGET RAILWAYS (2005-06)... contd.

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): जाइए, आप लोग जाइए, जाइए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: now, the Hon. Railway Minister will reply. *(Interruptions)* आप लोग बैठ जाइए। (व्यवधान...) आप लोग बैठिए। (व्यवधान...)। Mr.Narayanasamy, let the hon. Minister reply. *(Interruptions)*

SHRIMATI SAVITA SHARDA (Gujarat): Sir, this is not the way. *(Interruptions)*

श्री लालू प्रसाद: आप लोग जाना चाहते हैं तो जाइए। (व्यवधान...)

श्री उपसभापति: जब वे लोग जवाब सुनना ही नहीं चाहते तो हम लोग क्या कर सकते हैं।

श्री दीपांकर मुखर्जी: (पश्चिमी बंगाल): माननीय सभापति जी, श्री प्रमोद महाजन जी को रुकना चाहिए। (व्यवधान...) Sir, Shri Pramod Mahajan had initiated the debate. *(Interruptions...)* He initiated the debate *(Interruptions)*. He should listen to the reply. *(Interruptions)* Sir, you can request from the Chair... *(Interruptions)* Sir, he initiated the debate, let him be here. *(Interruptions)* Sir, Mr Pramod Mahajan is a very senior Member. He had initiated this debate. *(Interruptions)* I think that he should listen to the reply. *(Interruptions)*

MR DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, you are doing the same thing again. *(Interruptions)*

श्री रूद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): आप ही ने तो पहले कहा था कि तुम जाओ इसलिए हम जा रहे हैं। (व्यवधान...)

(At this stage, some hon. Members left the Chamber)

श्री लालू प्रसाद: माननीय उपसभापति जी, मुझे अब यह पक्का विश्वास हो गया है कि जब सदन में रेल मंत्री खड़े होते हैं तब भाजपा के लोगों को यह आशंका रहती है कि कहीं रेल इनके ऊपर न चढ़ जाए। जब-जब मैं खड़ा होता हूं तब-तब ये लोग पीठ दिखा कर चले जाते हैं। ये इतने बहादुर लोग हैं कि हमें फेस नहीं कर पाते।

उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने रेल बजट 2005-06, चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए सदन में प्रस्तुत की गई अनुदान व पूरक

मांगों पर हुई बहस में भाग लिया है और अपने बहुमूल्य विचारों से सदन को अवगत करवाया है। मुझे प्रसन्नता है कि अधिकांश माननीय सदस्यों ने यात्री भाड़े में वृद्धि न करने एवं बेरोजगार नवयुवकों, किसानों, दुग्ध उत्पादकों तथा ग्रामीण छात्र-छात्राओं के लिए दी गई रियायतों का स्वागत किया है। दूसरी ओर, कुछ माननीय सदस्यों ने चिंता भी व्यक्त की है कि यात्री भाड़े में वृद्धि न करने का भारतीय रेल की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ेगा हम रेलवे की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने यात्रियों पर बिना अतिरिक्त बोझ डाले, रेलवे की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है।

उपसभापति महोदय, रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर एवं माननीय सदस्य डा॰ विमल जालान जी के सुझाव का हम स्वागत करते हैं कि रेलवे के सर्वांगीण विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए एक दीर्घकालीन पंचवर्षीय योजना तैयार की जानी चाहिए और इसीलिए हमने एक पांच वर्ष की अवधि, यानी 2005 से 2010 तक के लिए, एक रेल आधुनिकीकरण योजना बनाई है, लेकिन हम अलग रेल बजट प्रस्तुत करने की परम्परा को समाप्त करने के श्री प्रमोद महाजन जी के विचार से कदापि सहमत नहीं हो सकते हैं।

महोदय, हवाई यात्रा करते हुए सपनों के महल बनाना,फील गुड करना अच्छी बात है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय रेल अभी भी देश के करोड़ों लोगों के परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि यह कहा जाए कि भारतीय रेल अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए रेल बजट के औचित्य पर सवाल उठाना सदन को स्वीकार्य नहीं हो सकता है।

चालू वर्ष के दौरान रेलवे की वित्तीय उपलब्धि – महोदय, माननीय सांसद श्री प्रमोद महाजन ने चालू वित्तीय वर्ष में रेलवे द्वारा दर्ज की गई शानदार उपलब्धि को यह कहकर खारिज कर दिया है कि रेलवे की उपलब्धि, जो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, उसका कारण भारतीय अंर्थव्यवस्था की सुधरी हुई स्थिति है, रेल की सुधरी हुई स्थिति नहीं है। महोदय, मेरे मित्र सदस्य ने अनचाहे मन से ही सही, यह स्वीकार तो किया है कि इस वर्ष अर्थव्यवस्था एवं भारतीय रेल की उपलब्धि सुधरी हैं। यह उपलब्धि बढ़ती आबादी और बढ़ते व्यापार के कारण ही नहीं, अपितु लाखों रेल कर्मियों के उद्योग व परिश्रम का फल है। महोदय, यह सही है कि हमारी जनसंख्या, हमारा व्यापार साल-दर-साल बढ़ रहा है। लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा कि रेलवे की इस वर्ष की उपलब्धि मात्र इन कारणों का ही परिणाम है महोदय, वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 में अर्थव्यवस्था की प्रगति दर क्रमशः 8.5 एवं 7 प्रतिशत रही है जबकि इन वर्षों में माल लदान से प्राप्त आय में क्रमशः 4.2 एवं 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार वर्ष 2004-05 में अर्थव्यवस्था की प्रगति दर 1.5 प्रतिशत घट जाने के बावजूद भी 2003-04 की तुलना में माल लदान की आय की प्रगति दर दोगुनी से अधिक

रही है। महोदय, हम माल-लदान की कार्यकुशलता के किसी भी मापदंड को लें, चाहे वह नेट टर्न किलोमीटर प्रति वैगन प्रतिदिन हो अथवा प्रति इंजन प्रतिदिन मालगाड़ी नेट टर्न किलोमीटर हो, हमने हर पैमाने पर उल्लेखनीय सुधार किया है। यही कारण है कि लम्बी अवधि के बाद चालू वर्ष में फ्रेट लोडिंग कि क्षेत्र में भारतीय रेल ने अर्थव्यवस्था की प्रगति दर से अधिक वृद्धि दर्ज कर माल परिवहन के बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने चालू वित्तीय वर्ष में माल लदान के लक्ष्य को 580 मिलियन टन से बढ़ाकर 600 मिलियन टन कर दिया है। इसी प्रकार यात्रियों की संख्या जहां 2003-04 में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वहीं 2004-05 में लगभग 6 प्रतिशत होने की सम्भावना है। इसी प्रकार कुल आमदनी में भी पिछले वर्ष दर्ज की गई 4 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में दोगुनी अर्थात् 9 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई है। महोदय, रेल परिवहन के प्रत्येक क्षेत्र में हासिल की गई इस बेहतरीन उपलब्धि के कारण ही आम जनता पर यात्री भाड़ा बढ़ाए जाने का बोझ डाले बिना आपरेटिंग रेशियो सुधरकर 91.2 प्रतिशत पर पहुंच गया है जो पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद का सबसे अच्छा स्तर है। महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने जानना चाहा है कि रेलवे के आधुनिकीकरण योजना के लिए बिना यात्री भाड़ा बढ़ाए राशि कहां से आएगी। महोदय, मैंने बाबा नागार्जुन की सलाह मानते हुए आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डालने का निर्णय लिया था। मैं उनकी ही कविता की कुछ पंक्तियां उद्धृत कर इस शंका का समाधान करना चाहता हूं:

"हम तो अपने ही बूते पर सस्ती प्लान बनाएंगे,
एक-एक कस्बे के अंदर सौ-सौ स्वर्ग बसाएंगे।"

माननीय सांसद श्री प्रमोद महाजन जी ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि वैगन टर्न राउंड को सात दिन से साढ़े छः दिन पर लाना मुश्किल है तो इसे रातोरात पांच दिन के स्तर पर कैसे लाया जाएगा। हमने माल गाड़ियों के टर्न राउंड टाइम को घटाकर 5 दिनों पर लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिसका उल्लेख मैंने अपने बजट भाषण में किया था। महोदय, चालू वर्ष में वैगन टर्न राउंड सात दिनों से घटाकर छः दिनों पर लाने का इतिहास हम रच चुके हैं। मुझे सम्मानित सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि मालगाड़ियों की टर्न राउंड अवधि फरवरी और मार्च के महीने में घटकर लगभग साढ़े पांच दिनों के स्तर पर पहुंच गई है। हम इसे पांच दिनों के स्तर पर लाने और भारतीय रेल को कार्यकुशलता के प्रत्येक क्षेत्र में विश्व के सबसे अच्छे स्तर पर लाने का हरसम्भव प्रयास करेंगे।

सार्वजनिक निजी भागीदारी के विकास के लिए गैर-परम्परागत स्त्रोतों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने एवं ग्राहकों को अच्छी सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी भागीदारी की अनेक योजनाएं प्रारम्भ करने की घोषणा की थी। अधिकांश सदस्यों ने इन योजनाओं की,

विशेषकर रेल भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना कर रेलवे की खाली पड़ी जमीन का सदुपयोग सुनिश्चित करने की सराहना की है। कुछ हलकों में इस बात की आशंका जताई गई है कि बिना वित्तीय प्रावधान के इन योजनाओं को अगले वर्ष पूरे देश में कैसे लागू किया जाएगा। महोदय, मैं माननीय सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि सार्वजनिक निजी भागीदारी की इन नई योजनाओं में भारतीय रेल को अपने हिस्से के रूप में पूर्व से ही उपलब्ध भूमि अथवा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इत्यादि उपलब्ध कराने हैं जबकि आवश्यक निधि का प्रबंध निजी भागीदार को करना है। इनसे न केवल बेकार पड़ी परिसम्पत्तियों का उपयोग कर आधुनिक संरचना का निर्माण होगा, अपितु रेलवे के लिए आय के गैर परम्परागत स्रोत भी प्राप्त होंगे। उदाहरण : बिहार राज्य के लिए स्थापित किए गए कम्प्यूटराइज्ड ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम से प्राप्त होने वाली राशि में से रेल टेल को प्रति कॉल 15 पैसे प्राप्त होते हैं। महोदय, सार्वजनिक निजी भागीदारी की ये योजनाएं "आम के आम, गुठलियों के दाम" की कहावत को चरितार्थ करती हैं।

उपसभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने वर्ष 2005-06 की वार्षिक योजना में बजटीय सहायता एवं योजना परिव्यय में की गई कटौती पर चिंता व्यक्त की है। मैं इस संबंध में वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहूंगा । चालू वर्ष में संशोधित अनुमानों के अनुसार भारतीय रेल को 8857 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता प्राप्त हुई है, जबकि अगले वर्ष 7231 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता प्राप्त होने का अनुमान है। लेकिन चालू वर्ष के यह संशोधित अनुमानों में ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामुला की नई रेल लाइन के लिए प्राप्त 700 करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित है जबकि अगले वर्ष के अनुमानित योजना परिव्यय में पूर्वोत्तर क्षेत्र की घोषित नई राष्ट्रीय परियोजनाओं एवं जम्मू कश्मीर की उक्त योजना के लिए प्राप्त होने वाली 1365 करोड़ रुपये की संभावित राशि सम्मलित नहीं है। इन योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि का आबंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा वर्ष के दौरान कार्य की प्रगति के आधार पर किया जायेगा। योजना आयोग द्वारा भी लाभप्रद योजनाओं के लिए स्पेशल परपज़ व्हीकल के माध्यम से वर्ष के दौरान 3 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराये जा सकते है। इसके अतिरिक्त रेलवे के वित्तीय निष्पादन में आये सुधार के फलस्वरूप योजना परिव्यय के लिए आंतरिक संसाधनों से प्राप्त होने वाली राशि 3775 करोड़ रुपये से बढ़कर 4718 करोड़ रुपये होने की संभावना हैं इतना ही नहीं, हमने विकास निधि में वर्ष 2004-05 के 715 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमानों में 1725 करोड़ रुपये और वर्ष 2005-06 में 1853 करोड़ रुपये के विनियोग का प्रावधान किया है। विकास निधि में 2005-06 के अंत में कुल 1953 करोड़ रुपये का अवशेष रहने की संभावना है जिसका उपयोग वर्ष के दौरान ली जाने वाली थ्रू पुट संवर्धन योजनाओं के लिए आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

उपसभापति महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी परिस्थिति में वर्ष 2005-06 में हमारा योजना परिव्यय चालू वर्ष से कम नहीं रहने दिया जायेगा एवं रेलवे की

आधुनिकीकरण योजना के क्रियान्वयन को राशि की कमी के कारण बाधित नहीं होने दिया जायेगा।

उपसभापति महोदय, कुछ माननीय सांसदों ने रेलवे पर संरक्षा तथा सुरक्षा की स्थिति एवं संरक्षा के लिए पर्याप्त आबंटन उपलब्ध नहीं कराने पर अपनी चिंता व्यक्त की है। रेलवे पर संरक्षा तथा सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने रेल संरक्षा की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं जिनके कारण परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है।

उपसभापति महोदय, विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत 17000 करोड़ रुपये की लागत पर लिए गए अनेक कार्य पूरे हो चुके हैं एवं सभी लंबित कार्यों को मार्च, 2007 तक पूरा करने के हर संभव प्रयास किये जायेंगे। वर्ष 2005-06 में रेल संरक्षा के लिए विशेष रेल संरक्षा निधि में 3522 एवं रेल संरक्षा निधि में 711 करोड़ रुपये अर्थात् कुल 4233 करोड़ रुपये के प्रावधान किये गये हैं जो कि कुल योजना परिव्यय के 28 प्रतिशत के बराबर हैं। इसके अलावा संरक्षा से संबंधित योजना शीर्षों पर आंतरिक स्त्रोतों से भी पर्याप्त परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जहां तक सुरक्षा का सवाल है, यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा बल में रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती अभियान एवं रेल सुरक्षा बल की आधुनिकीकरण योजना पूरे जोर से चल रही है।

उपसभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों द्वारा ऐसी आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि इस रेल बजट में कुछ राज्यों की उपेक्षा की गई है। इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि परियोजनाओं के लिए राशि उपलब्ध कराने में किसी राज्य विशेष के साथ पक्षपात नहीं किया गया है और विभिन्न राज्यों में चल रही परियोजनाओं के लिए धन का वितरण पूर्व निर्धारित नीति के अनुसार किया गया है जो कि राज्यों की जनसंख्या, क्षेत्रफल इत्यादि पर आधारित है। जैसा कि सदन को ज्ञात है कि रेलवे को चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लगभग 46000 करोड़ रुपये की जरूरत है। महोदय, प्रति वर्ष इन लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए जितनी राशि की व्यवस्था की जाती है उससे इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना संभव प्रतीत नहीं होता है। इस वर्ष हमने लगभग 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है जिसका एक हिस्सा प्रति वर्ष बढ़ती महंगाई के कारण हुई लागतों में वृद्धि को पूरा करने में ही लग जाता है। रेलवे अधिक से अधिक परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास कर रही है लेकिन माननीय सदस्य इस तथ्य से सहमत होंगे कि सारी परियोजनाओं को न तो एक साथ हाथ में लिया जा सकता है और न ही पूरा किया जा सकता है। हमें इन योजनाओं को पूरा करने के लिए एक नई रणनीति पर विचार करना होगा और सभी प्रकार के परंपरागत एवं गैर-परंपरागत स्रोतों से इस प्रकार धन जुटाना होगा जिससे इन्हें अगले पांच वर्षों में पूरा किया जा सके । इसी दृष्टिकोण से हमने लंबित परियोजनाओं को पांच साल के अंदर पूरा करने के लिए "सुदूर क्षेत्र रेल संपर्क योजना" को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।

महोदय, माननीय सदस्यों ने गत बजट में घोषित कुछ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एवं अन्य गाड़ियों के अभी तक प्रारंभ नहीं होने पर चिंता व्यक्त की है। महोदय, सदन को अवगत है कि कुछ राज्यों में हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनावों में आचार संहिता लागू रहने के कारण कुछ गाड़ियां प्रारंभ नहीं की जा सकीं। ऐसी कुछ गाड़ियां पिछले सप्ताह शुरू की जा चुकी हैं और शेष को भी इसी माह शुरू किया जाएगा। माननीय सदस्यों के अन्य सुझाव मुख्यतः अपने क्षेत्र या किसी खास स्थान के लिए नई रेलगाड़ी चलाने का अनुरोध, किन्हीं खास स्टेशनों पर किसी खास गाड़ी के ठहराव अथवा बड़े सरकारी अस्पतालों में उपचार के दौरान मरने वाले रोगियों के शवों को नजदीकी रेलवे स्टेशन तक की जाने वाली यात्रा के लिए 50 प्रतिशत रियायत को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने के बारे में है। माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए मैंने यात्रा में दी जाने वाली रियायत को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने अर्थात् मुफ्त किए जाने का निर्णय लिया है। जहां तक नयी रेलगाड़ियां चलाने की बात है, मैंने 54 अतिरिक्त गाड़ियां चलाने का प्रावधान इस बजट में किया है। साथ ही कई गाड़ियों का विस्तार एवं फेरे भी बढ़ाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 30 गाड़ियों की रफ्तार बढ़ायी गयी है। अधिक लोकप्रिय गाड़ियों में लगभग 400 अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाए जाएंगे। माननीय सांसदों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मैं कानपुर से मुंबई के बीच एक मेल ऐक्सप्रेस गाड़ी चलाने का प्रस्ताव करता हूं।

महोदय, जम्मू एवं कश्मीर के माननीय सांसदों ने पूर्ण हुई जम्मू से ऊधमपुर नई लाइन पर रेल सेवा शीघ्र आरंभ करने हेतु आग्रह किया है। मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है कि वे अप्रैल माह में इस लाइन का शुभारंभ ऊधमपुर से नई दिल्ली के बीच उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर करेंगे। माननीय सांसद श्री विजय दर्डा के अनुरोध का सम्मान करते हुए विदर्भ क्षेत्र के विकास हेतु मैं वर्धा से नांदेड़ वाया यवतमाल नई लाइन के सर्वेक्षण को अद्यतन किए जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही माननीय सांसदों की भावना को ध्यान में रखते हुए छतौनी से दुधाही वाया मधुबनी, धनहा, खेरा टोला एवं लक्ष्मीपुर से नवादा वाया जिनहरा, मोहनपुर, झाझा, बिसनपुर नई लाइन के सर्वेक्षण का प्रस्ताव करता हूं।

केरल राज्य के प्रो.पी.जे. कुरियन सहित अनेक माननीय सांसदों एवं माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेल बजट में केरल के हितों के नज़रअंदाज करने की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि क

रल के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा एवं पूर्व निर्धारित स्थिति के अनुसार केरल राज्य को जो राशि देय होती है, उसे उपलब्ध कराया जाएगा। केरल के माननीय सांसदों की भावनाओं के मद्देनजर मैं केरल के लिए निम्न प्रस्तावों की घोषणा करता हूं:

2625/2626 केरला एक्सप्रेस पूर्व की भांति दिल्ली से त्रिवेंद्रम के बीच चलेगी और इसका

चंडीगढ़ तक विस्तार नहीं किया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा राज्य के लोगों की मांग पर इसी महीने दिल्ली से त्रिवेंद्रम के बीच शुरू होने वाली केरल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का विस्तार चंडीगढ़ तक किया जाएगा। एर्णाकुलम और बेंगलोर के बीच एक साप्ताहिक गाड़ी चलाई जाएगी। 6603/6604 त्रिवेंद्रम-मंगलौर मावेली एक्सप्रेस को सप्ताह में दो से बढ़ाकर तीन दिन चलाने का प्रस्ताव है। क्विलोन-पुन्नलूर आमान परिवर्तन के कार्य को वर्ष 2005-06 में ही पूरा किया जाएगा। त्रिवेंद्रम से और अधिक गाड़ियां चलाने की मांग को ध्यान में रखते हुए एर्णाकुलम से कोट्टायम के रास्ते कायमकुलम की इकहरी लाइन के तीन डबलिंग कार्य पहले ही प्रगति पर हैं। इनके अलावा इस मार्ग पर 50 किलोमीटर लंबे दो नए डबलिंग कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं।

महोदय, केरल राज्य में 52 आर.ओ.बी. पर सम्प्रति कार्य चल रहा है। माननीय सदस्यों की मांग पर 5 नए आर.ओ.बी. पर भी स्वीकृति दी जा रही है। इस प्रकार केरल राज्य में 57 आर.ओ. बी. स्वीकृत हो जाएंगे, जो कि सभी राज्यों में सर्वाधिक हैं।

महोदय, आमान परिवर्तन के कार्यों की प्रगति का विवरण देते हुए बजट भाषण में मैंने उल्लेख किया था कि रूपसा-बांगरीपोसी के रूपसा-बारीपदा खंड के आमान परिवर्तन का कार्य चालू वर्ष में पूरा किया जा चुका है। इस विवरण में थोड़े संशोधन की ज़रूरत है। रूपसा-बांगरीपोसी के रूपसा-बारीपदा खंड के आमान परिवर्तन का कार्य पूरा होने के अंतिम चरणों में है तथा इस खंड पर रेलपथ का कार्य माह के अंत तक पूर्ण कर लिए जाने की संभावना है। इस संशोधन से माननीय सदस्यों को हुई असुविधा के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि रांची-लोहरदगा के आमान परिवर्तन का कार्य पूरा किया जा चुका है।

महोदय, मैंने माननीय सदस्यों द्वारा किए गए सुझावों एवं उठाए गए मुद्दों पर यथासंभव अपने विचार व्यक्त किए हैं, पर हो सकता है कि कुछ मुद्दे छूट गए हों। सदस्यों द्वारा उठाए गए स्थानीय मुद्दों पर संबंधित सदस्यों को पत्र लिखकर मैं वस्तुस्थिति से अवगत करा दूंगा। महोदय, रेल बजट को आम जनता एवं माननीय सदस्यों का व्यापक समर्थन मिला है, जिसके लिए मैं सभी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं तथा सदन से अनुरोध करता हूं कि रेलवे की वर्ष 2004-05 में खर्च के लिए अनुदान की पूरक मांगों व आने वाले वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए प्रस्तुत लेखानुदान से संबंधित विनियोग विधेयकों को लौटाने के लिए अपनी स्वीकृति दे।

GOVERNMENT BILLS

The Appropriation (Railways) Vote on Account Bill, 2005

AND

The Appropriation (Railways) Bill, 2005

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: